



भारत में वित्तीय समावेशन एवं जागरूकता का विश्लेषणात्मक अध्ययन

गरिमा सोनी¹

¹ रिसर्च स्कोलर, अर्थशास्त्र विभाग, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर.

ABSTRACT:

किसी अर्थव्यवस्था में वित्तीय समावेशन का विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है जिसके लिए आम जनता में वित्तीय होना बेहद जरूरी है ताकि मुद्रा के उपयोग करने के सही तरीके को समझने एवं समझाने की क्षमता का विकास हो सके। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ विशेष गुण या कौशल होते हैं जिनके माध्यम से वह सोच समझ कर धन या मुद्रा से संबंधित प्रभावशाली निर्णय ले सकता है। वित्तीय जागरूकता वित्तीय उत्पादों एवं सेवाओं की माँग का निर्माण करती है। वित्तीय जागरूकता प्रभावी पूँजी निर्माण का द्वार है जो रोजगार एवं गरीबी निवारण में सहयोग प्रदान करती है। ग्लोबल फाइनेंशियल लिटरेसी एक्सीलेंसी सेंटर के अनुसार भारत में वित्तीय जागरूकता की दर व्यक्ति आबादी में मात्र 24 प्रतिशत ही है जोकि विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है। यह अंतर ग्रामीण और शहरी भारत में अधिक है। महानगरों में वित्तीय जागरूकता अधिक जबकि गाँवों एवं पिछड़े राज्यों में कम है। प्रस्तुत लेख में भारत में वित्तीय समावेशन एवं जागरूकता के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी।

KEYWORDS:

वित्तीय जागरूकता, भारतीय रिज़र्व बैंक, वित्तीय स्थिरता और विकासा

प्रस्तावना

भारतीय रिज़र्व बैंक इस हेतु अनेक प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन करती है। इसके लिए वित्तीय समावेशन और वित्तीय जागरूकता का तकनीकी समूह एवं वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद् समन्वित रूप से काम करती है। वित्तीय समावेशन योजना चालू की गई है। इसके माध्यम से वित्तीय जागरूकता की दर को बढ़ाया जा सके और आम नागरिकों को वित्तीय शिक्षा दी जा सके क्योंकि प्रगतिशील अर्थव्यवस्था के लिए यह मुख्य घटक है। वित्तीय जागरूकता का सीधा सा अर्थ है धन या मुद्रा के उपयोग करने के सही तरीके को समझने एवं समझाने की क्षमता का होना ताकि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ विशेष गुण या कौशल होते हैं जिनके माध्यम से वह सोच समझ कर धन या मुद्रा से संबंधित प्रभावशाली निर्णय ले सकता है। यदि कोई व्यक्ति प्रभावी वित्तीय नियोजन करता है, ऋण का उचित प्रबंधन करता है, ब्याज की गणना आसानी से कर लेता है और वह धन के समय मूल्य को जानता है तो यह माना जाता है कि वह वित्तीय रूप से साक्षर है।

विस्तृत अर्थ में इसमें बजट बनाना, खर्चों पर नियंत्रण रखना और सेवानिवृत्ति की सही योजनाओं का निर्माण करना भी इसमें शामिल है। इससे व्यक्ति को बैंकों द्वारा प्रदत्त उत्पादों एवं सेवाओं की आवश्यकताओं तथा लाभों की जानकारी मिलती है। जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय समावेशन को गति मिलती है। यह सत्य है कि समाज के प्रत्येक वर्ग को किसी न किसी रूप में वित्तीय जागरूकता की आवश्यकता रहती है। वित्तीय जागरूकता का लक्ष्य सुलभ वित्तीय साधन एवं साक्षरता के माध्यम से वित्तीय जागरूकता समावेशन को आसान बनाना है।

अध्ययन की आवश्यकता –

प्रस्तुत अध्ययन की आवश्यकता के निम्नलिखित आधार बिन्दु है।

1. वित्तीय जागरूकता क्या है? को जानना।
2. भारत में वित्तीय जागरूकता की स्थिति को जानना।
3. वित्तीय जागरूकता में सहयोग करने वाली संस्थाओंको जानना।

भारत में वित्तीय जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र की स्थापना की गई। यह एक गैर-लाभकारी कंपनी है जोकि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अंतर्गत बनाई गई है। इस कंपनी को प्रमुख वित्तीय नियामको, भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी, आईआरडीए और पीएफआरडीए द्वारा सहयोग दिया जाता है। यह कंपनी वित्तीय जागरूकता स्तर का पता लगाने के लिए सर्वे करती है एवं जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करती है। यह विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में वित्तीय प्रबंधन अवधारणाओं

को पढ़ाने के लिए पाठ्यक्रमों को विकसित करती है। वित्तीय धोखाधड़ी से सुरक्षा को अधिक प्राथमिकता प्रदान करती है। वित्तीय जागरूकता के कार्यक्रम कनाडा, जापान, सऊदी अरब, अमेरिका आदि देशों में भी संचालित किए जाते हैं। यद्यपि आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन ने सामान्य वित्तीय जागरूकता सिद्धान्त के विकास के माध्यम से वित्तीय शिक्षा और साक्षरता मानकों में सुधार के तरीके प्रदान करने के लिए वर्ष 2003 में एक परियोजना की शुरुआत की थी। मार्च 2008 से वित्तीय शिक्षा के लिए अन्तर्राष्ट्रीय गेटवे प्रारम्भ किया है। इसका कार्य विश्व में वित्तीय शिक्षा कार्यक्रमों की संचूना एवं अनुसंधान का विकास करना है।

शोध समीक्षा:-

मीणा राजगोपाल एवं शदीद यशोदा 2012 ने वित्तीय जागरूकता के लिए राष्ट्रीय रणनीति में लिखा है कि भारत एक विशाल राष्ट्र है तो इसे भी अन्य राष्ट्रों की भाँति वित्तीय जागरूकता के लिए एकीकृत और समन्वित राष्ट्रीय नीति अपनाने की आवश्यकता है। इस हेतु केंद्र और राज्य सरकारें वित्तीय संस्थाएँ, शिक्षाविद् और अन्य सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थाओं को एक साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। एक विशाल शिक्षा अभियान के माध्यम से लोगों को वित्तीय सेवाओं के माध्यम से धन के अधिक कारण प्रबंधन करने में मदद की जा सकती है। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के अनुसार वित्तीय जागरूकता वित्तीय जागरूकता, ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण एवं व्यवहार का संयुक्त एवं समग्र रूप है। जिसकी सहायता से वित्तीय फैसले लिए जा सके और व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सके। वित्तीय शिक्षा के माध्यम से लोग वित्तीय जागरूकता प्राप्त करते हैं। विश्व में चैक गणराज्य, नीदरलैंड, स्पेन और ब्रिटेन जैसे देश वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति जारी कर चुके हैं।

स्मृति कम्बोज 2014 ने शोध-पत्र करंट सेनेरियो ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी इन इण्डिया में बताया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक वित्तीय उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सराहनीय कार्य कर रहा है। वह स्वयं सहायता समूह एवं गैर सरकारी संस्थानों के माध्यम से वित्तीय शिक्षा दे रहा है। भारत में वित्तीय जागरूकता को बढ़ाने के लिए अधिक शोधपरक कार्य करने की आवश्यकता है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस हेतु वित्तीय जागरूकता एवं साख कार्डसिल 2009 की स्थापना की है। इसके बाद अनेक बैंकों के द्वारा वित्तीय जागरूकता के कार्य में सहयोग प्रदान किया है जिनमें बैंक ऑफ इण्डिया का अभय, आईसीआईसीआई बैंक का दिशा, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा महाराष्ट्र में परामर्श केंद्र खोलना प्रमुख है। ये सभी ग्राहकों को वित्तीय उत्पादों की जानकारी प्रदान करते हैं।

अजीज अब्दुल एन. पी. एवं अख्तर जावेद एस. एम. 2021 ने लेख डिटरमिनेशन ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी इन रूरल इण्डिया में बताया है कि वित्तीय जागरूकता जाति, धर्म,

लिंग, शिक्षा स्तर आदि सभी आर्थिक चरों के बावजूद भी एक महत्वपूर्ण कौशल है लेकिन इसका विकास ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम हुआ है। इसलिए ऐसे क्षेत्रों में सरकार, शैक्षणिक संस्थानों और वित्तीय सेवा प्रदाता संस्थानों के द्वारा वित्तीय जागरूकता के कार्यक्रमों को लागू किया जाना चाहिए परन्तु आज सभी वित्तीय संस्थान वित्तीय समावेशन पर अधिक ध्यान दे रहे हैं जबकि उन्हें वित्तीय जागरूकता पर अधिक ध्यान देना चाहिए क्योंकि वित्तीय जागरूकता ही वित्तीय समावेशन को आसान एवं अधिक बनाती है।

वित्तीय जागरूकता की आवश्यकता के कारण:-

1. धन में धोखाधड़ी से बचाव के लिए।
2. सही वित्तीय प्रबंधन के लिए।
3. आय सृजन एवं पूँजी निर्माण की दर में वृद्धि के लिए।
4. आय-व्यय में नियंत्रण के लिए।
5. भविष्य की सुरक्षा के लिए बचतों का निवेश करने की सही प्रक्रिया जानने के लिए।
6. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण के लिए।
7. आय के उत्तम स्रोतों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए।
8. बड़े तर एवं लाभकारी विकल्पों के चयन के लिए।

वित्तीय समावेशन रणनीति के प्रमुख लक्ष्य:-

1. वित्तीय सेवाओं, विभिन्न वित्तीय उत्पादों एवं उनकी विशिष्टताओं की जानकारी के लिए उपभोक्ताओं को जागरूक बनाना एवं शिक्षित करना।
2. जानकारी को व्यवहार में बदलने की प्रवृत्ति को विकसित करना।
3. वित्तीय सेवाओं के लाभार्थियों के रूप में उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों एवं जिम्मेदारियों की जानकारी देना।

समकों का विश्लेषण

भारतीय रिज़र्व बैंक देश की जनता के बीच विभिन्न विषयों पर वित्तीय संदेशों का प्रचार-प्रसार करने के लिए वर्ष 2016 से प्रतिवर्ष वित्तीय जागरूकता सप्ताह का आयोजन कर रहा है। इस वर्ष यह सप्ताह 14-18 फरवरी 2022 को मनाया गया। इसकी विषय-वस्तु डिजिटल चुनो, सुरक्षा के साथ रही। यह विषय वित्तीय शिक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्य नीति 2020-2025 के उद्देश्यों में से एक है। इसके तहत डिजिटल लेनदेन की सुविधाएँ, डिजिटल लेनदेन की सुरक्षा और ग्राहकों के संरक्षण के बारे में बताया गया। इसी वर्ष भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय जागरूकता संदेश पुस्तिका का तीसरा संस्करण भी जारी किया। इसके अतिरिक्त बेसिक फाइनेंशिएल लिटरेसी, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और गोइंग डिजिटल पर आडियो विजुअल सेवा भी है जो वित्तीय जागरूकता के संदेश देती है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने "वित्तीय शिक्षा रिपोर्ट 2020-25 के लिए राष्ट्रीय नीति" नाम से एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया है कि देश में वित्तीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 5 ब् पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये 5 C है- Content सामग्री, Capacity क्षमता, Community समुदाय, Communication संचार एवं Collaboration सहयोग प्रमुख है।

इसके लिए वित्तीय समावेशन और वित्तीय जागरूकता का तकनीकी समूह एवं वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद् (2012) समन्वित रूप से काम करती है। इसके अलावा भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय जागरूकता योजना भी चला रखी है जो विद्यालयों, महाविद्यालयों, महिलाओं, लक्षित समूहों, गरीबों, ग्रामीणों आदि के लिए वित्तीय एवं बैंकिंग अवधारणाओं के बारे में जानकारी प्रदान करती है।

विवरण	वर्ष 2013 में वित्तीय साक्षरता की दर प्रतिशत में	वर्ष 2019 में वित्तीय साक्षरता की दर प्रतिशत में	विवरण	वर्ष 2013 में वित्तीय साक्षरता की दर प्रतिशत में	वर्ष 2019 में वित्तीय जागरूकता की दर प्रतिशत में

सामान्य जाति	24	29	पुरुष	23	29
अन्य पिछड़े वर्ग	17	26	महिला	16	21
अनुसूचित जाति	14	25	ग्रामीण	15	24
अनुसूचित जन जाति	15	27	शहरी	25	33

स्रोत- सर्वेक्षण पर आधारित।

ग्लोबल फाइनेंशिएल लिटरेसी एक्सीलेंसी सेंटर के अनुसार भारत में वित्तीय जागरूकता की दर व्यस्क आबादी में मात्र 24 प्रतिशत ही है जोकि विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है। महानगरों में वित्तीय जागरूकता अधिक एवं गरीब और पिछड़े राज्यों में कम पाई जाती है। ऐसी ही रिपोर्ट भारतीय वित्तीय जागरूकता एवं समावेशन सर्वे रिपोर्ट 2019 में बताया गया है कि अखिल भारतीय स्तर पर वित्तीय जागरूकता की दर 27 प्रतिशत है जबकि यह ग्रामीण क्षेत्रों में 24 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्रों में 33 प्रतिशत है। महिलाओं में यह दर 21 प्रतिशत और पुरुषों में 29 प्रतिशत है। आयु वर्ग के आधार पर विश्लेषण करने पर तो 18-29 वर्ष के आयु वर्ग में 30 प्रतिशत, 30-49 वर्ष के आयु वर्ग में 27 प्रतिशत, 50-59 वर्ष के आयु वर्ग में 25 प्रतिशत, 60-69 वर्ष के आयु वर्ग में 23 प्रतिशत, 70-80 वर्ष के आयु वर्ग में 27 प्रतिशत अखिल भारतीय स्तर पर है। जबकि राजस्थान में यह दर मात्र 20 प्रतिशत ही है। इस दर में अब काफी बदलाव हुआ है जैसा कि तालिका में स्पष्ट है-

निष्कर्ष

यह सत्य है कि वित्तीय जागरूकता प्रभावी पूँजी निर्माण का द्वार है जो श्रम शक्ति को प्रभावित कर कौशल में विकास करती है जो अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार एवं गरीबी निवारण में सहयोग प्रदान करती है। वित्तीय गतिविधियों की जागरूकता में शिक्षा की अहम भूमिका होती है। सरकार, बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों को अपने वित्तीय जागरूकता कार्यक्रमों को इस प्रकार लागू करने का प्रयास करना चाहिए कि कम पढ़े-लिखे एवं साक्षर भी आसानी से समझ सके। वित्तीय जागरूकता में बुद्धिमानी से व्यय, बचत, ऋण, बीमा, पेंशन आदि जीवन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। महिलाओं को अधिक जागरूक करना आवश्यक है। भारत जैसे देश में विस्तृत सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं के अभाव में प्रत्येक व्यक्ति को वित्तीय साक्षर होना अति आवश्यक है। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधा, वित्तीय संस्थानों का सक्रिय योगदान, वित्तीय सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँच होना भी आवश्यक है।

REFERENCES

1. मीणा राजगोपाल एवं शदीद यशोदा, वित्तीय जागरूकता के लिए राष्ट्रीय रणनीति, पत्र सूचना कार्यालय, मुंबई, भारत सरकार, 18 जुलाई 2012
2. स्मृति कम्बोज, कंट सेनेरियो ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी इन इण्डिया, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंट रपेन्योरशिप एण्ड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट, वाल्यूम 1, इश्यू 1, पृष्ठ संख्या 61-68, 2014
3. अजीज अब्दुल एन. पी. एवं अख्तर जावेद एस. एम., डिटरमिनेशन ऑफ फाइनेंशिएल लिटरेसी इन रूरल इण्डिया, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फाइनेंशिएल इंजीनियरिंग, वाल्यूम 8, इश्यू 2, पृष्ठ संख्या 2150009.1-2150009.17 2021
4. वित्तीय जागरूकता गाइड, ग्रामीण आयोजना एवं ऋण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई, भारत सरकार, जनवरी 2013, पृष्ठ संख्या 1-36
5. प्रेस प्रकाशनी, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई, भारत सरकार, 2021-22/1705
6. माइकल एवं अन्य, स्कूल ऑफ स्टडी एण्ड फाइनेंशिएल लिटरेसी, जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स एण्ड इकोनॉमिक्स एज्यूकेशन रिसर्च, 11(3), पृष्ठ संख्या 29-37

7. राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र रिपोर्ट 2015

8. भारत में वित्तीय जागरूकता और समावेशन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019